

**भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 4812
दिनांक 28.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

क्षेत्रीय सामरिक सहयोग में वृद्धि

4812. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा विशेष रूप से खाड़ी और मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रों में क्षेत्रीय सामरिक सहयोग बढ़ाने के लिए क्या पहल की गई है;
- (ख) भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) से भारत और अन्य देशों के बीच संपर्क और व्यापार संबंधों में किस तरह सुधार होने की उम्मीद है;
- (ग) इस क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
- (घ) अपने कूटनीतिक प्रयासों द्वारा सरकार भूमध्य सागर और उससे इतर के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए किस तरह योजना बना रही है; और
- (ड.) भारत और चर्चित क्षेत्रों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में भारतीय मूल के लोगों द्वारा निभाई गई भूमिका का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**विदेश राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्गेरिटा)**

(क) और (घ) खाड़ी, 'मेना' और भूमध्य सागर क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने अपने कूटनीतिक प्रयासों का लाभ उठाकर कई देशों के साथ बहुआयामी रणनीतिक सहभागिता की है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक संबंधों को बढ़ाना, राजनयिक हितों को आगे ले जाना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, और अधिक आर्थिक एवं निवेश संवर्धन, ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करना, लोगों के बीच संबंधों को गहरा करना, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार में सहयोग का विस्तार करना, अवसंरचना का विकास करना और वैश्विक प्रभाव बढ़ाना है। इन देशों के साथ भारत की रणनीतिक सहभागिता का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

भारत आई2यू2 (भारत, इज़राइल, यूएई और यूएसए) पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे छह पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य अवसंरचना के आधुनिकीकरण, उद्योगों को कार्बन मुक्त करने, सार्वजनिक

स्वास्थ्य में सुधार और महत्वपूर्ण, उभरती एवं हरित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता को जुटाना है।

(ख) नई दिल्ली में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका के नेताओं ने 9 सितंबर 2023 को एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की, जिसके तहत एक नया भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईईसी) विकसित करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई गई। आईएमईईसी में दो अलग-अलग गलियारे शामिल होंगे, पूर्वी गलियारा भारत को खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इन गलियारों का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, दक्षता बढ़ाना, लागत कम करना, क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना, व्यापार पहुंच बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना है जिसके परिणामस्वरूप एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का परिवर्तनकारी एकीकरण होगा।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईसी) के संचालन के लिए सहयोग से संबंधित एक अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क करार (आईजीएफए) पर 13 फरवरी 2024 को हस्ताक्षर किए गए। इस रूपरेखा के मुख्य तत्वों में एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सहित एक संभार-तंत्रीय मंच का विकास एवं प्रबंधन तथा आईएमईईसी को मूर्त रूप देने के लिए सभी प्रकार के सामान्य कार्गो, बल्क, कंटेनर और तरल बल्क को संभालने के लिए आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं का प्रावधान शामिल है। आईएमईईसी के कार्यान्वयन में कई हितधारक शामिल हैं और यह प्रारंभिक चरण में है।

ग) सरकार के पास इस क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण है। इनमें, *अन्य बातों के साथ-साथ*, सभी क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति (महासागर) पहल, (सागर सिद्धांत "क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास" का विस्तार), हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी पहल, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए), कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) और रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर करना शामिल है। हिंद महासागर के देशों के कल्याण और प्रगति के लिए भारत की प्रतिबद्धता, जिसमें प्रथम सहायताप्रदाता और निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में भूमिका शामिल है, अन्य बातों के अलावा महासागर दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत का उद्देश्य क्षेत्र में अधिक समृद्धि को बढ़ावा देना और हिंद महासागर को समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय(यूएनसीएलओएस) का सम्मान करते हुए एक स्वतंत्र और खुले स्थान के रूप में स्थापित करना है।

ड) दुनिया के सबसे बड़े प्रवासी समुदाय के रूप में हम प्रवासी भारतीयों के साथ अपने जुड़ाव में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। 35.4 मिलियन का मजबूत प्रवासी भारतीय समुदाय (15.9 मिलियन एनआरआई और 19.5 मिलियन पीआईओ) राष्ट्र की प्रगति में एक अमूल्य भागीदार है। भारतीय प्रवासी अन्य बातों के अलावा धन प्रेषण, व्यापार, निवेश, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विशेषज्ञता और ज्ञान के हस्तांतरण के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देकर आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करते हैं, इस तरह से वे भारत के राष्ट्रीय

हित को आगे बढ़ाने के लिए एक सेतु का काम करते हैं। एक सफल, समृद्ध और प्रभावशाली प्रवासी समुदाय एक परिसंपत्ति है। भारत अपने प्रवासी नेटवर्क का दोहन करके और ऐसे समृद्ध प्रवासी समुदाय से मिलने वाली सॉफ्ट पावर के उत्पादक उपयोग से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। सरकार के प्रयासों का उद्देश्य प्रवासी क्षमता का पूर्ण उपयोग करना भी है।

क्र. सं.	देश का नाम	2014 से अन्य देशों के साथ भारत की रणनीतिक सहभागिता	ऐसी रणनीतिक सहभागिताओं की घोषणा में निहित उद्देश्य
खाड़ी			
1	कुवैत	रणनीतिक सहभागिता	दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा के दौरान भारत-कुवैत द्विपक्षीय संबंधों का स्तर रणनीतिक सहभागिता स्तर तक बढ़ गया। राजनीति, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, संस्कृति, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक और संरचित सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करना।
2	कतर	रणनीतिक सहभागिता	कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान 18 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की स्थापना संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। यह करार राजनीति, व्यापार, ऊर्जा, निवेश, सुरक्षा, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कतर के साथ सहयोग को गहरा करेगा।
3	सऊदी अरब	रणनीतिक सहभागिता परिषद (एसपीसी) करार	29 अक्टूबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री की रियाद यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक सहभागिता परिषद (एसपीसी) करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत भारत-सऊदी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय परिषद की स्थापना की गई। एसपीसी करार का उद्देश्य रणनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के स्तर को बढ़ाना और आपसी राजनीतिक विश्वास को गहरा करना है। इस करार में दोनों देशों की विकास रणनीतियों के बीच तालमेल का लाभ उठाया गया है और राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, सुरक्षा, सैन्य और सांस्कृतिक

			क्षेत्र में उनके बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया है।
4	संयुक्त अरब अमीरात	व्यापक रणनीतिक सहभागिता - 2017	भारत के 68वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अबू धाबी के तत्कालीन क्राउन प्रिंस, महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और अधिक गहरा, व्यापक और मजबूत बनाने के लिए व्यापक रणनीतिक सहभागिता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
मेना क्षेत्र			
1	मिस्र	रणनीतिक सहभागिता	जनवरी 2023 में मिस्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्देल फत्तह अल-सीसी की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान, भारत और मिस्र के संबंध रणनीतिक सहभागिता स्तर तक उन्नत हो गए। इसका उद्देश्य राजनीतिक, विकास, आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक, तकनीकी, रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद-रोध सहित भारत और मिस्र के बीच विस्तारित, पारस्परिक रूप से लाभकारी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को संस्थागत बनाना था।
2	इजराइल	रणनीतिक सहभागिता	जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक सहभागिता स्तर तक पहुंच गए। विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, साइबर सुरक्षा उद्यमिता, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में साझेदारी की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए व्यापक आधार वाले संबंध का निर्माण करना।
भूमध्य सागर क्षेत्र			
1	ग्रीस	रणनीतिक सहभागिता	अगस्त 2023 में माननीय प्रधानमंत्री की ग्रीस की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत और ग्रीस द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक सहभागिता के स्तर तक ले गए। दोनों देशों और वहां के लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मधुर और घनिष्ठ संबंधों की नींव पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत-ग्रीस द्विपक्षीय संबंधों को "रणनीतिक सहभागिता" के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

2	इटली	रणनीतिक सहभागिता	<p>मार्च 2023 में भारत और इटली के संबंधों को रणनीतिक सहभागिता के स्तर तक ले जाया गया।</p> <p>भारत, इटली को यूरोप और भूमध्यसागरीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार मानता है। इटली, इंडो-पैसिफिक पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और भारत को इस क्षेत्र में एक प्रमुख हितधारक मानता है। रणनीतिक सहभागिता, द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में गहनता और गति लाएगी और वैश्विक मुद्दों का समाधान करने के हमारे संयुक्त प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगी।</p>
---	-------------	------------------	--
